

माननिय राजस्व मण्डल महोदय म० प्र० ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिला-  
रीवा म० प्र०

XX



10/सिंग/सिंगरौली/सुन/2017/1789

- 1- राजनाथ शाह तनय स्व. नाहर शाह उम-83वर्ष,
  - 2- श्रीभई शाह तनय स्व. इन्दर शाह उम-54वर्ष,
- दोनों पेशा- खेती, स० गनियारी, तहसील सिंगरौली,  
जिला सिंगरौली म० प्र०

अपीलांतगण  
सिंगरौली

बनाम  
=====

म० प्र० शासन ----- ~~रेसपॉण्डेंट~~ और सिंगरौली

आवेदक का कोर्ट से  
आवेदन कुल सादर  
काया पेशा/ 12.6.17

कलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर  
(सर्किल कोर्ट) रीवा

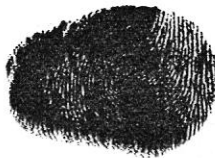
सिंगरौली  
अधीन विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त रीवा  
संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक- 1313/अपील/  
12-13 में पारित आ. दि. 30.5.2017  
-----  
सिंगरौली  
अधीन अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959  
-----

मान्यवर, सिंगरौली  
अधीन अंतगण की ओर से निम्नलिखित अपील प्रस्तुत है:-----

§ 1 §-यहकि निर्णय/आदेश अधिनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया एवं सही तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

§ 2 §-यहकि अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के उक्त आ. दि. 26.08.13 एवं तहसीलदार के उक्त आ. दि. 04.09.13 को अपीलाधीन आदेश में न तो निरस्त ही किया है और न स्वीकार ही किया है ऐसी स्थिति में उक्त दोनों आदेश प्रभावी रहते हुये प्रचलित विधि के तहत तहसील न्यायालय को कोई भी नवीन आदेश पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है और वह कोई आदेश पारित ही नहीं कर सकता इस कारण अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

राजस्व मण्डल



RTI-सिंगरौली 2पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

III/10210/1310/रीवा/2017/1789  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक 1789-तीन/2017 निगरानी

जिला -सिंगरोली

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	<p>यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1313/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-5-17 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 30-5-17 में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त ने उभय पक्ष के बीच हुये राजीनामे के आधार पर अपील प्रकरण का निराकरण किया है। व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 43 में बर्जन है कि दोनों पक्षों के मध्य कोई सहमति हो जाती है और समझौता के आधार पर न्यायलय द्वारा आदेश पारित किया जाता है, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।</p> <p>3/ उपरोक्त कारणों से निगरानी प्रचलन-योग्य एवं ग्राह्य-योग्य न होने से निरस्त की जाती है।</p>	<p>सदस्य</p>